[2016] 2 एस. सी. आर. आई 027

अमानुल्लाह और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(2016 की आपराधिक अपील संख्या 299)

12 अप्रैल, 2016

[वी. गोपाल गौड़ा और उदय उमेश ललित, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-को रद्द करना संज्ञान आदेश-महिला की हत्या के खिलाफ अपील-मृतक के पति द्वारा प्राथमिकी जिसमें आरोप लगाया गया है कि हत्या अपीलार्थी नं. 2 और एक अन्य व्यक्ति-जाँच के दौरान, गवाहों ने सी. जे. एम. के सामने गवाही दी कि मृतक के पति ने मृतक की हत्या कर दी-4 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र-आरोप पत्र दायर करने के बाद, पति ने गवाहों को परेशान करना शुरू कर दिया-धमकी देने के लिए, वह अपीलार्थी नं. 1 पिस्तौल और खंजर के साथ-उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी-पति और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र-सीजेएम ने उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया। धारा 482 के अन्तर्गत दायर याचिका- आदेश को रद्द करने के लिए-उच्च न्यायालय ने संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया-इसके खिलाफ अपील-चाहे पोषणिय और क्या उच्च न्यायालय ने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। धारा 482- अदालत ने कहाअभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चला कि सी. जे. एम. ने अदालत के समक्ष रखी गई केस डायरी, आरोप पत्र और अन्य सामग्री के अवलोकन के बाद अभियुक्त-व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लिया-संज्ञान लिया गया, क्योंकि अभियुक्त-व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था- अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को आरोप पत्र के साथ दर्ज करके सीजेएम द्वारा संज्ञान लेने से पहले विधिवत विचार किया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। 482-इसके अलावा, उच्च न्यायालय एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में

विफल रहा कि मामला हत्या के गंभीर अपराध से संबंधित है और इससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

आपराधिक कानूनः अपराध का संज्ञान-अपराध का संज्ञान लेने के स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य-अदालत ने कहा संज्ञान लेने के स्तर पर, अदालत को मामले के गुण-दोष में नहीं पड़ना चाहिए पुलिस द्वारा, उनके द्वारा दायर आरोप पत्र में, उस विशेष मामले में अभियोजन की सफलता दर की गणना करने की दृष्टि से-इस स्तर पर, अदालत का कर्तव्य यह पता लगाने की सीमा तक सीमित है कि क्या उसके सामने रखी गई सामग्री से, मामले में आगे बढ़ने की दृष्टि से आरोपी के खिलाफ कथित अपराध बनाया गया है या नहीं।

आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की अदालत में जाने का अधिकार-तीसरे पक्ष को अपील करने की अनुमति देने की शक्ति- अदालत ने कहाःयह राज्य का कर्तव्य है कि अपराधी के खिलाफ उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मामला दर्ज किया जाए-न्यायालय को मामले से प्रामाणिक संबंध रखने वाले किसी भी तीसरे पक्ष को अनुमति देने में उदार होना चाहिए। पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अपील को बनाए रखने के लिए-हालाँकि, किसी तीसरे पक्ष को अपील करने की अनुमति देने का उपयोग अच्छी सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए-विचाराधीन मामले से असंबद्ध या अभियुक्त के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायत रखने वाले व्यक्तियों की जाँच की जानी चाहिए।

शब्द और वाक्यांश -लोकस स्टैंडी-का अर्थ-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय

1. उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। इसने सीजेएम द्वारा पारित संज्ञान आदेश को सही परिप्रेक्ष्य में उसके सामने रखी गई सामग्री की सराहना किए बिना रद्द करने में गलती की है। उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया, अर्थात् 17.10.2008 को, अपीलार्थी नं.1 को आरोपी द्वारा कथित रूप से धमकी दी गई थी जिसके लिए उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 26 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत विभिन्न गवाहों के बयान इस आशय के थे कि मृतक की हत्या उसके पति के अलावा किसी और ने नहीं की थी। द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करके, आरोप पत्र के साथ दायर किया गया था, जिस पर सीजेएम द्वारा

संज्ञान लेने से पहले विधिवत विचार किया गया था और इसलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। इसके अलावा, उच्च न्यायालय एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहा कि मामला हत्या के गंभीर अपराध से संबंधित है और इससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपने समक्ष रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रहा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। [पारस 27 से 29] [1046-ए-ई]

पी. एस. आर. साधनानथम बनाम अरुणाचलम (1980) 3 एस. सी. सी. 141; रमाकांत राय आर.मदन राय और अन्य 2003 (4) पूरक। एससीआर 17:(2003) 12 एससीसी 395; हरियाणा राज्य v. भजन लाल 1990 (3) पूरक। एससीआर 259:1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335; राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर 2013 (3) एस. सी. आर. 52:(2013) 3 एस. सी. सी. 330-पर निर्भर था। एशर सिंह बनाम ए. पी. राज्य 2004 (2) एस. सी. आर. 1180:(2004) 11 एससीसी 585; रमाकांत वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (16) एस. सी. आर. 1013:(2008) 17 एस. सी. सी. 257; आशीष चड्ढा बनाम आशा कुमारी और अन्य। 2011 (13) एस. सी. आर. 417:(2012) 1 एससीसी 680; जे. के. इंटरनेशनल बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य। 2001 (2) एससीआर 90:(2001) 3 एससीसी 462; एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और अन्य बनामनागपुर जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड और अन्य। 2008 क्राई एल. जे. 995-संदर्भित।

(1980) 3 एससीआर 141	**भरोसा किया**	**पारा 15**
2003 (4) पूरक एससीआर 17	**भरोसा किया**	**पारा 15**
2004 (2) एससीआर 1180	**संदर्भित**	**पारा 15**
2008 (16) एससीआर 1013	**संदर्भित**	**पारा 15**
2011 (13) एससीआर 417	**संदर्भित**	**पारा 15**
2001 (2) एससीआर 90	**संदर्भित**	**पारा 20**

2008 क्राई. एल.जे. 995	**संदर्भित**	**पारा 20**
1990 (3) पूरक एससीआर 259	**संदर्भित**	**पारा 21**
2013 (3) एससीआर 52	**भरोसा किया**	**पारा 26**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2016 की आपराधिक अपील संख्या 299।

सी. आर. में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 08.12.2010 से विविध 2009 का सं. 5777।

नीरज शेखर, आशुतोष ठाकुर, राणा प्रशांत, रोहीत कुमार सिंह, अनिमेष कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए गोपाल सिंह, शिवम सिंह, सुश्री वर्षा पोद्दार, शिशिर पिनाकी, सनजय जैन।

न्यायालय का निर्णय वी. गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह आपराधिक अपील विशेष अनुमति द्वारा आक्षेपित निर्णय और दिनांक 08.12.2010 के आदेश के विरुद्ध जो पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार द्वारा पारित आपराााक विविध 2009 की संख्या 5777 जिसमे विद्वत अपर मुख्य न्यायिक दण्डधिकारी रोसडा, बिहार द्वारपा सिधिया पुलिस कांड संख्या 37/2008 में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 10.11.2008 को अपास्त/दरकिनार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 द्वारा दायार उक्त याचिका अपराधिक विविध को स्वीकार किया गया और सिंधिया पुलिस कांड संख्या 37/2008 मे आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया। बिहार ने सिंघिया पुलिस केस नंबर 37/2008 में आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया।

3. पक्षकारों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी दावों की सराहना करने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैंः

अभियोजन पक्ष का मामला है कि मुख्तार 29 मार्च, 2008 को गांव नवदेगा में अपने रिश्तेदार के घर गया और वहीं रहा। 30 मार्च, 2008 को लगभग 12 (बजे) उसके चाचा मोहम्मद हासिम ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया कि उसकी पत्नी की हालत गंभीर है

और उसे इलाज के लिए सिंघिया ले जाया जा रहा है। मुख्तार को सिंघिया पहुंचने के लिए कहा गया। यह मुखबिर द्वारा आरोप लगाया गया है कि सिंघिया पहुंचने पर उसे न तो अपनी पत्नी मिली और न ही अपने चाचा। चाचा से पूछताछ करने पर उसे अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और देखा कि उसकी पत्नी का शव पड़ा है। उसके चाचा ने उसे बताया कि उसकी पत्नी तमन्ना खातून (अब मृत) मक्का के खेत में गई थी, जहां वह अपने मुंह और नाक को से बांध कर पड़ी थी दुपट्टा उसे एक हीरा सदा (पीडब्ल्यू-2) ने देखा, जो अपनी बेटी के साथ लौट रहा था। मृतक के शोर मचाने पर उसने शोर मचाया और उसी मुखबिर के चाचा मोहम्मद हासिम अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और तमन्ना खातून को इलाज के लिए सिंघिया ले गए। सिंघिया ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। 30. 03. 2008 को मृतक के पति मुख्तार द्वारा मोहम्मद राजू और मोहम्मद हलीम उर्फ मंगनू-अपीलार्थी नं.2 के विरुद्ध एफ आइ आर दाायर किया इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में 'भ. द.स.') के साथ पढ़ें।

4. जांच के दौरान, कई गवाहों ने न्यायिक दंडाधिकारी रोसेरा के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मृतक के पति मुख्तार ने अपनी पत्नी की हत्या की है।

5. 30.09.2008 को आरोप पत्र सं. 111/2008 पुलिस द्वारा रोसेरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में मोहम्मद हासिम, मोहम्मद नूर हसन, मोहम्मद सफीक और झोठी सादा के खिलाफ एफआईआर संख्या 37/2008 के संबंध में आरोप पत्र संख्या 111/2008 दायर किया गया था।

6. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मुख्तार ने गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। धमकीन को ध्यान मे रखते हुए अपीलकर्ता नं. 1,17 अक्टूबर, 2008 को वह पिस्तौल और खंजर के साथ अपने घर पहुंचा। अपीलकर्ता नं.1 ने शोर मचाया और यह सुनकर सह-ग्रामीणों ने मुख्तार का पीछा करने के बाद उसे हथियारों के साथ पकड़ लिया। सिंघिया पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 26 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर संख्या 104/08 दर्ज की गई थी।

7. दिनांक 31.10.2008 को, एक अनुपूरक आरोप पत्र सं.126/2008, एफआईआर संख्या 37/2008 के संबंध में पुलिस द्वारा मोहम्मद मुख्तार उर्फ मुन्ना, मोहम्मद नज़रे आलम और मोहम्मद फारुख के खिलाफ विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम के समक्ष दायर किया गया था

8. विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद दिनांक 10.11.2008 कोउन्होंने मुख्तार और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत संज्ञान लिया।

9. विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पीएस केस नं. 37/2008 में पारित संज्ञान आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी नं. 2 से 9 ने आपराधिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आपराधिक विविध पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दरवाजा खटखटाया.विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के दिनांक 10.11.2008 के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध सं. 577/2009।

10. उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.12.2010 के अपने आदेश द्वारा विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करके कथित याचिका को स्वीकार किया और आपराधिक अभियोजन को भी रद्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित, यहां अपीलकर्ता, जो हितबद्ध निजी पक्ष हैं, ने विभिन्न आधारों का आग्रह करते हुए यह अपील दायर की है।

11. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता श्री नीरज शेखर ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि एफआईआर और आरोप पत्र प्रत्यर्थी नं. २-९ के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं.उन्होंने कहा कि जब आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मामला दिखाते हैं, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

12. आगे यह प्रतिवाद किया गया कि उच्च न्यायालय ने विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने में गलती की है क्योंकि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां मनमानी या मनमानी के अनुसार कार्य करने के लिए मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक कार्यवाहियों को

रद्द करने की शक्ति का उपयोग कम और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में।

13. विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रतिवाद किया गया कि अपराध का संज्ञान लेने के स्तर पर, केवल जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, यह अवधारित करना उचित नहीं होगा कि दोषसिद्धि स्थायी है या नहीं। उच्च न्यायालय ने सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करके इसकी सराहना करने में गलती की है न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का प्रकटन नहीं करता है या उसमें लगाए गए अभिकथन तुच्छ, तंग करने वाले या दमनकारी पाए जाते हैं। इस स्तर पर, विचारण से पहले, यह पता लगाने के लिए कि क्या मामला दो-सिद्धि या दो-मुक्ति में समाप्त होगा, मामले का कोई सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए।

14. आगे यह प्रतिवाद किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी और सक्रिय भागीदारी को स्थापित करती है, जिसे उच्च न्यायालय समझने में विफल रहा है।

15. विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों को इस कारण से इस अपील को बनाए रखने का अधिकार है कि अपीलार्थियों का अपीलार्थी नं.1 को मुख्तार और अपीलकर्ता नं.मुख्तार ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में अपीलार्थी 2 को झूठा फंसाया था। नीचलीी अदालत द्वारा पारित आक्षेपित संज्ञाना आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार करने से दोनों अपलार्थी व्यथित हैं। **उपर्युक्त के समर्थन में उन्होंने पी. एस. आर. साधनांथम बनाम अरूणाचलम वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने आगे रमाकांत राय वनाम मदन राय और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होने आगे ईशर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य रमाकांत वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और आशीष चड्ढा बनाम आशा कुमारी और अन्य पर भरोसा किया।**

16. इस मामले में एफआईआर मुख्तार की पत्नी की हत्या के लिए दो व्यक्तियों, मोहम्मद राजू और मोहम्मद हालिम के खिलाफ मुख्तार के बयान पर आधारित है और यह आईपीसी की धारा 302 और 120बी के तहत दर्ज किया गया था और इसे धारा 34 के साथ पढ़ा गया था। प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर पिनाकी का कहना है कि उत्तर देनेवाले प्रतिवादीगण का नाम एफ. आई.आर में नही विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक

दंडाधिकारी उन्होने आगे कहा है कि दनांक् 11.04.2008 को मुखविर -मुख्तार ने रोसेरा के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की। कथित विरोध याचिका में अदालत के संज्ञान में यह लाया गया था कि मूल रूप से उसने पांच व्यक्तियों मोहम्मद राजू, मोहम्मद हलीम उर्फ मंगनू, खालिद गुलाब, अबू कयूम और मोहम्मद हुसैन के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। जांच के क्रम को गलत दिशा में मोड़ दिया गया ताकि प्रतिवादी न. २-९ को गलत तरीके से फंसाया जा सके।

17. विद्वत वकील द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया कि तत्काल मामला एक अद्वितीय मामला है क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया जाता है और उनके अलावा मामले में प्रशिक्षित गवाहों का एक और सेट पेश किया गया है, जो घटना के गवाह नहीं हैं और उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि मुखबिर हो सकता है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों और सामग्री की उचित जांच के बाद यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी नं.2-9 केवल संदेह पर आधारित है और इसलिए, इसने उनके खिलाफ कार्यवाही को उचित रूप से खारिज कर दिया है।

18. उसने आगे प्रस्तुत किया कि घटना के बाद मृतक के पिता मंजूर आलम ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में अपनी बेटी की हत्या के लिए मुख्तार के पति को दोषी नहीं ठहराया। जहां तक अन्य प्रत्यर्थियों का संबंध है, मुखबिर के अलावा, वे सभी मामले के लिए अजनबी हैं और वास्तविक आरोपी व्यक्तियों के इशारे पर स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

19. विद्वत वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक के पिता और माता ने नोटरी पब्लिक के समक्ष एक स्टांप पेपर पर अपना बयान दिया है कि उनकी बेटी अपने पति के साथ सौहार्दपूर्ण वैवाहिक जीवन और उसे उसके पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी दहेज की मांग के संबंध में यातना नहीं दी जा रही थी।

20. निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा करके इन्हें प्रस्तुत किया गया **जे. के. इंटरनेशनल बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एक अन्य बनाम नागपुर जिला सुरक्षा बोर्ड और एक अन्य वाले मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी की। नागपुर जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड और एक अन्य** विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे

प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी वाद हेतुक के साथ अपने वास्तविक संबंध का खुलासा करने में विफल रहे हैं, पीड़ित के साथ सटीक रूप से और इस प्रकार, इस अपील को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है.इसलिए इस अपील को इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

21. अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक तर्कसंगत आदेश है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है.हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में उच्च न्यायालय का निर्णय भी न्यायोचित है। **इसलिए, अपनी अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।**

22. प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद दोनों पक्षों की ओर से आग्रह किया गया कि हमारे विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठेंगेः

1. क्या यह अपील अपीलार्थियों द्वारा अधिस्थिति के आधार पर कायम रखी जा सकती है?

2. क्या इस मामले में उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण किया है?

3. किस क्रम में?

<u>**बिंदु संख्या 1 का उत्तर**</u>

23. 'लोकस स्टैंडी' शब्द एक लैटिन शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ 'खड़े होने का स्थान' है। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 834 में 'लोकस स्टैंडी' शब्द को कार्रवाई करने या अदालत में पेश होने के अधिकार या क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। लोकस स्टैंड का पारंपरिक दृष्टिकोण यह रहा है कि जो व्यक्ति व्यथित या प्रभावित है उसे न्यायालय के समक्ष खड़े होने का अधिकार है, अर्थात् यह कहना कि उसे केवल न्याय के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। बाद में, इस न्यायालय ने न्याय उन्मुख दृष्टिकोण के साथ 'लोकस स्टैंड' के संबंध में सख्त नियम में ढील दी, जिससे समाज के किसी भी व्यक्ति को उन लोगों के लिए न्याय की मांग करने की अनुमति मिल गई जो खुद से संपर्क नहीं कर सकते थे। अब हमारा ध्यान आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किए जाने वाले आपराधिक मुकदमे की ओर जाता है।

चूंकि, अपराध को समाज के खिलाफ किया गया एक गलत कार्य माना जाता है, इसलिए राज्य द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जाता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। यहां मुख्य बिंदु यह है कि यदि राज्य इस संबंध में विफल रहता है और वाद हेतुक के साथ वास्तविक संबंध रखने वाला पक्ष, जो न्यायालय के आदेश से व्यथित है, पृष्ठ 14 को नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य की दया पर और बिना किसी विकल्प के न्याय के लिए अपीलीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इस संबंध में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पी. एस. आर. साधननाथम के मामले (ऊपर) में उपर्युक्त तथ्य स्थिति पर विस्तार से विचार किया है। सुसंगत पैरा 13,14 और 25 इस प्रकार हैंः

> "13. यह सच है कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग पर कड़ी सतर्कता, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के उच्च स्तर पर, बनाए रखी जानी चाहिए और आम तौर पर मध्यस्थता करने वालों को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी सच है कि दांडिक अधिकारिता में यह सख्ती लागू होती है क्योंकि इस न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय से जीवन या स्वतंत्रता को असुधार्य क्षति हो सकती है।

> "14. ऐसा कहने के बाद, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब कई सामाजिक प्रदूषक अनसुलझी शिकायत की नई समस्याएं पैदा करते हैं जब राज्य आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए एकमात्र भंडार बन जाता है। कभी-कभी नौकरशाही अधिकारियों की उदासीनता, कभी-कभी उच्च पदाधिकारियों के राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में मामला ले जाने से इनकार किया जा सकता है, भले ही मुकदमा का न्याय इसे उचित ठहराए। जैसा कि लॉर्ड शॉक्रॉस ने एक बार लिखा था, आपराधिक कानून का उपयोग निजी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत प्रतिशोध में एक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि लॉर्ड शॉक्रॉस ने एक बार लिखा था, एक स्वतंत्रता अभियोजन प्राधिकरण के अभाव में प्रत्येक नागरिक के लिए आसानी से सुलभ, अभिव्यक्ति का एक व्यापक अर्थ पेज 15 है अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 136 के लिए आवश्यक है। ऐसी अधिकारिताएं हैं जिनमें निजी व्यक्ति-केवल राज्य ही नहीं-दांडिक कार्यवाहियों को कानूनी रूप दे सकते हैं। विधि सुधार आयोग (आस्ट्रेलिया) ने अपने परिचर्चा पत्र सं. 4 में 'न्यायालयों तक पहुंच-1 स्थायी:जनहित वाद (पब्लिक इंटरेस्ट सूट्स) ने लिखा हैः

> वर्तमान समय में सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति दंडाधिकारी अदालत में कार्यवाही शुरू कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। उस अधिकार को बनाए रखने के लिए तर्क स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों पर उत्पन्न होता है-बड़े मामले और अक्सर छोटे मामले। सबसे बड़े मामले सरकार को छूने वाले हैं-एक वाटरगेट या एक पॉल्सन। चाहे वे कानूनी रूप से कितने ही स्वतंत्रता क्यों न हों, वे किसी भी सार्वजनिक अधिकारी, पुलिस या अभियोजन प्राधिकारी को किसी सरकारी पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए और सरकारी धन पर निर्भर होना चाहिए। इसके अधिकारियों के अनिवार्य रूप से सरकार के साथ व्यक्तिगत संबंध होंगे। वे 'प्रतिष्ठान' का हिस्सा होंगे। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राजनीतिक प्रभाव वाले किसी मामले पर मुकदमा न चलाने के निर्णय को सही या गलत रूप में राजनीति से प्रेरित माना जाएगा। कभी-कभार दुरूपयोग की संभावना को स्वीकार करते हुए आयोग इस तरह के मामले को अदालतों में ले जाने के किसी नागरिक के अधिकार को बनाए रखने में योग्यता देखता है।

यहां तक कि अंग्रेजी प्रणाली भी, जैसा कि चर्चा पत्र द्वारा इंगित किया गया है, किसी निजी नागरिक को अभ्यारोपण फाइल करने की अनुमति देती है। हमारे विचार में विंटेज इंग्लिश लॉ में व्यथित व्यक्ति की अवधारणा में जो संकीर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उन्हें हमारी लोकतांत्रिक स्थिति में उदारीकरण की आवश्यकता है। दाभोलकर के मामले में इस न्यायालय ने एक व्यापक अर्थ प्रदान किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने "बेकर बनाम कार के प्रसिद्ध मामले में" "खड़े होने" "के प्रति प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण। " में ढील दी। लार्ड डेनिंग के मामले में गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल बनाम पियरा सर एन जी ने इस प्रकार कहाः"

> ....".व्यथित व्यक्ति\" "शब्दों का व्यापक अर्थ है और उनका प्रतिबंधात्मक निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए। " ""इसमें निश्चित रूप से केवल एक ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, जो उन चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है, जिनका उससे कोई लेना-देना नहीं है"

प्रो.एस. ए. डी. स्मिथ का भी यही मत हैः

> "सभी विकसित कानूनी प्रणालियों को जनहित के दो पहलुओं के बीच टकराव को समायोजित करने की समस्या का सामना करना पड़ा है-कानून के प्रवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए व्यक्तिगत नागरिकों को प्रोत्साहित करने की वांछनीयता

> और पेशेवर वादी को प्रोत्साहित करने की अवांछनीयता और उन मामलों में अदालतों के अधिकार क्षेत्र का आहवान करने के लिए दख़ल देने वाला। ”

प्रो. एच. डब्ल्यू. आर. वेड ने इसी प्रकार का टिप्पण कियाः

> “दूसरे शब्दों में, उत्प्रेषण स्थान की संकीर्ण अवधारणा तक सीमित नहीं है। इसमें एक्टीओ पॉपुलैरिस का एक तत्व शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आवेदक के व्यक्तिगत अधिकारों से परे देखता है-यह अवर न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक प्राधिकारियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोककर न्याय की मशीनरी को उचित कार्य व्यवस्था में रखने के लिए बनाया गया है। ”

दाभोलकर के मामले में हममें से एक ने अपनी अलग राय में लिखाः

> “यह आशंका कि सार्वजनिक अर्थ के साथ कानूनी स्थिति को व्यापक बनाने से मुकदमेबाजी की बाढ़ आ सकती है जो न्यायाधीशों को अभिभूत कर सकती है, गलत है क्योंकि सार्वजनिक शरारत को दबाने के लिए सार्वजनिक रूप से न्यायालय का सहारा लेना न्याय प्रणाली के लिए एक श्रद्धांजलि है। “

यह विचार आस्ट्रेलियन विधि सुधार आयोग द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है।

25. भारत में भी दांडिक विधि में राज्य को अभियोजक के रूप में परिकल्पित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, राज्य की मशीनरी को पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर गतिशील बनाया जाता है। यदि मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है और अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के खिलाफ अपील करने के अधिकार को बारीकी से सीमित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन राज्य उच्च न्यायालय में अपील करने का हकदार था और शिकायतकर्ता ऐसा तभी कर सकता था जब उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की जाए। अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन राज्यों में निहित अपील का अधिकार अब उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को दी गई अनुमति के अध्यधीन बना दिया गया है। शिकायतकर्ता इस शर्त के अधीन है कि उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। अपील करने के अधिकार पर इस प्रकार लगाई गई बेड़ियों के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश करने की अनिच्छा है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक

आरोप से बरी कर दिया गया है, भले ही वह उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया हो, मामले की आगे की जांच के लिए चिंता और तनाव है। भारत के विधि आयोग ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया और यह नोट करते हुए कि संहिता ने किसी व्यथित व्यक्ति को कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति देने के रूप में कुछ अपवादों को मान्यता दी कतिपय मामलों में कार्यवाहियों और शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति के साथ दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देने के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की सामान्य वांछनीयता को अभिव्यक्त किया। यह इंगलैंड और अन्य देशों में प्राप्त कामन लॉ न्यायशास्त्र के प्रति निर्देश करता है जहां दो-मुक्ति के विरुद्ध अपील का सीमित अधिकार राज्य में निहित था और जहां सामान्य प्रशासन के हित में सामान्य महत्व के विधि के बिन्दु का विनिश्चय करने और दांडिक विधि के समुचित विकास पर बल दिया जाता था। लेकिन साथ-साथ विधि आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि यदि दो-मुक्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार बरकरार रखा जाता है और शिकायतकर्ता को विस्तारित किया जाता है तो विधि को तार्किक रूप से ऐसे मामलों को भी शामिल करना चाहिए जो शिकायत पर संस्थित नहीं किए गए हैं। यह पाया गयाः

> “स्पष्ट अन्याय के चरम मामले, जहां सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है और पीड़ित पक्ष को लगता है कि इस मामले पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है, हमारे विचार में, सरकार की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्याय के प्रशासन में विश्वास को प्रेरित करने और बनाए रखने के लिए, निजी पक्षकार को दी गई अनुमति के साथ अपील करने के सीमित अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए और किसी व्यथित व्यक्ति की प्रेरणा पर निजी शिकायत पर या अन्यथा शुरू किए गए मामलों को अपनाना चाहिए। ”

तथापि, जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अधिनियमित की गई थी, जैसा कि हमने देखा है, प्राइवेट पक्षकारों के मामले में परिवादी तक अपील करने के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। यह कानून की नीति का वास्तविक संकेत है।

(इस न्यायालय द्वारा दिए गए बल पर)

24. सके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने रमाकांत राय के मामले में (पूर्वोक्त) इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

"12. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए राज्य से भिन्न किसी प्राइवेट पक्षकार की सक्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। हम संदेह में कोई सार नहीं देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में निहित अपीलीय शक्ति को विशिष्ट कानूनों के तहत अपीलीय न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली साधारण अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक पूर्ण शक्ति है, जिसका प्रयोग सामान्य कानून के दायरे से बाहर किया जा सकता है। न्याय (दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह देखें) संविधान का अनुच्छेद 136 न तो किसी को इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार देता है और न ही किसी को न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने से रोकता है। शक्ति इस न्यायालय में निहित है लेकिन न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार किसी में निहित नहीं है। इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग इस बारे में किसी सीमा तक सीमित नहीं है कि कौन इसका आह्वान कर सकता है.जहां उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय से न्याय की गंभीर हत्या हुई है, वहां यह न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने से परहेज नहीं कर सकता और इस आधार पर हस्तक्षेप करने से परहेज नहीं कर सकता कि राज्य ने नहीं बल्कि किसी निजी पक्ष ने न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग किया है। हमें जरा भी संदेह नहीं है कि हम हितबद्ध निजी पक्षकारों के अनुरोध पर भी उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णयों के खिलाफ अपीलें स्वीकार कर सकते हैं। परिस्थिति यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबंध नहीं करती है। किसी प्राइवेट पक्षकार की प्रेरणा पर अधीनस्थ न्यायालय की अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्ति के प्रश्न से कोई सुसंगतता नहीं है। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि मोहन लाल बनाम अजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय ने एक निजी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप किया। यह आशंका व्यक्त की गई कि यदि निजी पक्षकारों के कहने पर दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की अनुमति दी जाती है तो अपीलों की बाढ़ आ सकती है। हम इस आशंका को साझा नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों को इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार किया जाता है, चाहे

वह राज्य हो या निजी पक्ष जो इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करता है, और विशेष अनुमति अनुक्रम के रूप में नहीं दी जाती है, लेकिन केवल अच्छे और पर्याप्त कारणों से, इस न्यायालय की सुस्थापित प्रैक्टिस पर। ”

ईशर सिंह के मामले में (पूर्वोक्त) इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 न तो किसी को इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार देता है और न ही किसी को इसका अवलंब लेने से रोकता है। मामले का प्रासंगिक पैरा 29 इस प्रकार हैः

"29. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए राज्य से भिन्न किसी प्राइवेट पक्षकार की सक्षमता के बारे में कई मामलों में संदेह व्यक्त किया गया है। हम संदेह में कोई सार नहीं देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में निहित अपीलीय शक्ति के तहत अपीलीय न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली साधारण अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह न्याय की मांग को पूरा करने के लिए सामान्य कानून के दायरे से बाहर प्रयोग की जाने वाली पूर्ण शक्ति है। (देखिए दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह)संविधान का अनुच्छेद 136 न तो किसी को इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार देता है और न ही किसी को न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने से रोकता है। शक्ति इस न्यायालय में निहित है लेकिन न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार किसी में निहित नहीं है। इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग इस बारे में किसी सीमा तक सीमित नहीं है कि कौन इसका आह्वान कर सकता है.जहां उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय से न्याय की गंभीर हत्या हुई है, वहां यह न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने से परहेज नहीं कर सकता और इस आधार पर हस्तक्षेप करने से परहेज नहीं कर सकता कि राज्य ने नहीं बल्कि किसी निजी पक्ष ने न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग किया है। हमें जरा भी संदेह नहीं है कि हम हितबद्ध निजी पक्षकारों के अनुरोध पर भी उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णयों के खिलाफ अपीलें ग्रहण कर सकते हैं। यह स्थिति कि संहिता किसी निजी पक्षकार की प्रेरणा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबंध नहीं करती है, अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्ति के प्रश्न से सुसंगत नहीं है। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि मोहन लाल बनाम

अजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय ने एक निजी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप किया। यह आशंका व्यक्त की गई कि यदि निजी पक्षकारों के कहने पर दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की अनुमति दी जाती है तो अपीलों की बाढ़ आ सकती है। हम इस आशंका को साझा नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार की जाती है, चाहे वह राज्य हो या निजी पक्ष जो इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करता है, और विशेष अनुमति अनुक्रम के रूप में नहीं दी जाती है, लेकिन केवल अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए दी जाती है, जो इस न्यायालय की प्रैक्टिस द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं।

(इस न्यायालय द्वारा दिए गए बल पर)

इसके अतिरिक्त, रमा कांत वर्मा के मामले में (उपर्युक्त) इस न्यायालय ने पूर्वोक्त मत को दोहराया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अपीलीय शक्ति केवल एक साधारण अपीलीय शक्ति नहीं है जिसका प्रयोग विशिष्ट कानूनों के अधीन अपीलीय न्यायालयों और अपीलीय अधिकरणों द्वारा किया जाता है। यह एक पूर्ण शक्ति है जिसका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधारण कानून के दायरे से बाहर किया जा सकता है। मामले का प्रासंगिक पैरा 16 इस प्रकार हैः

“रमाकांत राय बनाम मदन राय में यह था अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गएः(एससीसी पृष्ठ 402, पैरा 12)

"12. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए राज्य से भिन्न किसी प्राइवेट पक्षकार की सक्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। हम संदेह में कोई सार नहीं देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में निहित अपीलीय शक्ति को विशिष्ट कानूनों के तहत अपीलीय न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली साधारण अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह न्याय की मांग को पूरा करने के लिए 'साधारण कानून के दायरे से बाहर प्रयोग करने की पूर्ण शक्ति है' (देखें दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह) संविधान की धारा 136 न तो किसी को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार देती है और न ही में बाधा डालती है।

न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने से कोई भी व्यक्ति.शक्ति इस न्यायालय में निहित है लेकिन न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार किसी में निहित नहीं है। इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग इस बारे में किसी सीमा तक सीमित नहीं है कि कौन इसका आह्वान कर सकता है.जहां उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय से न्याय की गंभीर हत्या हुई है, वहां यह न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने से परहेज नहीं कर सकता और इस आधार पर हस्तक्षेप करने से परहेज नहीं कर सकता कि राज्य ने नहीं बल्कि किसी निजी पक्ष ने न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग किया है। हमें जरा भी संदेह नहीं है कि हम हितबद्ध निजी पक्षकारों के अनुरोध पर भी उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णयों के खिलाफ अपीलें स्वीकार कर सकते हैं। यह स्थिति कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') किसी निजी पक्षकार की प्रेरणा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबंध नहीं करती है, अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्ति के प्रश्न के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि मोहन लाल बनाम अजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय ने एक निजी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप किया। यह आशंका व्यक्त की गई कि यदि निजी पक्षकारों के कहने पर दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की अनुमति दी जाती है तो अपीलों की बाढ़ आ सकती है। हम इस आशंका को साझा नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों को इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार किया जाता है, चाहे वह राज्य हो या निजी पक्ष जो इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करता है, और विशेष अनुमति अनुक्रम के रूप में नहीं दी जाती है, लेकिन केवल अच्छे और पर्याप्त कारणों से, इस न्यायालय की सुस्थापित प्रैक्टिस पर। "

(इस न्यायालय द्वारा दिए गए बल पर)

25. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता साथ-साथ प्रत्यर्थियों द्वारा मामले की विधि पर विचार करने के बाद, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के प्रकाश में, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों को इस अपील को बनाए रखने का अधिकार है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों का हाथ में मामले से सटीक संबंध है और इस प्रकार, इस अपील को बनाए रखने का अधिकार है.अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय, अर्थात्, पी. एस. आर. साधनांथम (पूर्वोक्त) और रमाकांत राय,

ईशर सिंह, रमाकांत वर्मा (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर सही रूप से भरोसा किया है.इसके अतिरिक्त, यहां यह मत व्यक्त करना प्रासंगिक है कि यह कड़ाई से प्रगणित करना संभव नहीं हो सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 को लागू करते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील बनाए रखने का किसको अधिकार होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक मामले के पास तथ्यों का एक अनूठा सेट है। पूर्वोक्त मामले की विधि से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को किसी भी तीसरे पक्ष को अनुमति देने में उदार होना चाहिए, जिसके पास वास्तविक मामले से संबंधित अपील को पर्याप्त न्याय प्रदान करने की दृष्टि से बनाए रखने के लिए.तथापि, तीसरे पक्ष को अपील बनाए रखने की अनुमति देने की इस शक्ति का प्रयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। विचाराधीन मामले से असंबद्ध या अभियुक्त के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायत रखने वाले व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में कड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है।

<u>बिंदु संख्या 2 का उत्तर</u>

26.रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि विद्वत सीजेएम/ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी-व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के समक्ष प्रस्तुत अन्य सामग्री के अवलोकन के बाद लिया। संज्ञान लिया गया, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि संज्ञान लेने के चरण में, अदालत को उस विशेष मामले में अभियोजन की सफलता दर की गणना करने की दृष्टि से, पुलिस द्वारा तैयार किए गए मामले के गुणों में नहीं जाना चाहिए.इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य तक सीमित है यह पता लगाने की सीमा कि क्या उसके समक्ष रखी गई सामग्री से, अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध मामले को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया है या नहीं.इस न्यायालय ने भजन लाल के मामले (ऊपर) में सीआरपीसी की धारा 482 से संबंधित कानून के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया है। सुसंगत पैरा 102 और 103 इस प्रकार हैंः

> 102. अध्याय XIV के अधीन संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों के निर्वचन की पृष्ठभूमि में और अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित विनिश्चयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की

या संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों की, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम दृष्टांत के माध्यम से ऐसे मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत या कठोर सूत्र अधिकथित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन, भले ही वे उनके फेस वैल्यू पर लिए गए हों और उनके संपूर्णता में स्वीकार किए गए हों, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साथ किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटन नहीं करती है और पृष्ठ 27 को न्यायोचित ठहराती है। संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच न्यायोचित ढहराती है।

(3) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अविवादित अभिकथन और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाते हैं।

(4) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते किंतु केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के अधीन यथाअनुध्यात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

(5) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अधीन कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित की जाती है) के किसी उपबंध में संस्था और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध है, व्यथित पक्षकार की शिकायत के प्रभावी निवारण का उपबंध करते हुए कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन उत्कीर्ण है।

(7) जहां किसी दांडिक कार्यवाही पर असद्भाव के साथ स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण उसके प्रति ईर्ष्या करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से संस्थित की जाती है।

103. हम इस आशय की एक चेतावनी भी देते हैं कि किसी दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम और सावधानी/चौकसी से किया जाना चाहिए। और वह भी विरले मामलों में से विरले मामलों में कि न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच आरंभ करना न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।

इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर के मामले में कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं जिनका अनुसरण उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित रूप में किया जाएः

"29. वर्तमान मामले में जिस मुद्दे की जांच की जा रही है, वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, यदि वह जारी करने की प्रक्रिया के चरण में, या सुपुर्दगी के चरण में, या आरोप तय करने के चरण में भी किसी आरोपी के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत को रद्द करने का विकल्प चुनता है। ये सभी वास्तविक मुकदमा शुरू होने से पहले के चरण हैं। यही मानक स्वाभाविक रूप से बाद के चरणों के लिए भी उपलब्ध होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित शक्ति के दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि यह अभियोजन/शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना

अभियोजन/शिकायतकर्ता के मामले को खारिज कर देगा। इस तरह का संकल्प हमेशा सावधानी, जिम्मेदारी और सतर्कता/चौकसी के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि अदालत द्वारा पेश की गई सामग्री ऐसा है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उसकी/उनकी प्रतिरक्षा ठोस, तर्कसंगत और अदम्य तथ्यों पर आधारित है, प्रस्तुत की गई सामग्री ऐसी है जो अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज और विस्थापित करेगी और उत्पादित सामग्री ऐसी है जो अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार और उलट देगी। अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को बिना किसी साक्ष्य को दर्ज किए खारिज करना, खारिज करना और खारिज करना पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए, बचाव पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, उसका खंडन नहीं किया जाना चाहिए था, या वैकल्पिक रूप से, स्टर्लिंग और त्रुटिहीन गुणवत्ता की सामग्री होने के कारण, उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता था.अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है वह ऐसी होनी चाहिए जो किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को आरोपों के वास्तविक आधार को खारिज करने और झूठे होने की निंदा करने के लिए प्रेरित करे। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा उसे इस तरह की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए राजी करेगी, क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सकेगा।

30. उपर्युक्त कंडिकायो में दिए गए तथ्यों के आधार पर, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त द्वारा अभिशप्त किए जाने के लिए की गई प्रार्थना की सत्यता का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित कदमों को रेखांकित करेंगेः

30.1 पहला कदमःक्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है वह ठोस, तर्कसंगत और अक्षम्य है अर्थात सामग्री स्टर्लिंग पक्की/असली/विश्वस्त और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है?

30. 2.दूसरा कदमःक्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगा अर्थात् सामग्री के लिए पर्याप्त है? क्या शिकायत में निहित तथ्यात्मक दावों को अस्वीकार करना और उन्हें अस्वीकार करना अर्थात सामग्री ऐसी है जो किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा कहकर खारिज करने और उसकी निंदा करने के लिए प्रेरित करेगी?

30. 3.तीसरा कदमःक्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है उसका अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है और/या सामग्री ऐसी है कि अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा इसका खंडन उचित नहीं किया जा सकता है?

30. 4.चौथा कदमःक्या मुकदमे की कार्यवाही से अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा और न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा?

30. 5.यदि सभी कदमों का उत्तर सकारात्मक है तो उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए उसे राजी करना चाहिए।

(इस न्यायालय द्वारा दिए गए बल पर)

27. दोनों पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी दावों, ऊपर संदर्भित केस लॉ और रिकॉर्ड अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा ४८२ के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसने विद्वत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने में गलती की है सीजेएम ने सही परिप्रेक्ष्य में उसके समक्ष रखी गई सामग्री की सराहना किए बिना.उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है, अर्थात्, 17 अक्टूबर, 2008 को, अपीलकर्ता नं.1 को कथित तौर पर आरोपी मुख्तार द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके लिए शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 26 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 104/08 दर्ज की गई थी। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष विभिन्न गवाहों के बयान हैं कि मृतक की हत्या उसके पति मुख्तार के अलावा किसी और ने नहीं की है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करके जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर संज्ञान लेने से पहले

सीजेएम द्वारा विधिवत विचार किया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

28. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहा है कि मामला हत्या के गंभीर अपराध से संबंधित है और उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही पर होनी चाहिए। इसमें हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जो कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है।

<u>बिंदु संख्या 3 का उत्तर</u>

29. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय भजन लाल के मामले में (ऊपर) इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रकाश में उसके समक्ष रखी गई सामग्री का मूल्यांकन करने में विफल रहा है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी अधिकारिता से बाहर हो गया है। इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जाता है।

30. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विद्वत सीजेएम/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को भेजा जाता है।

अपील की अनुमति है।

देविका गुजराल

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।